दैनिक जागरण

ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा अज्ञान है

एक और आघात

यह एक और बड़ा आघात ही है कि पुलवामा में भीषण आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों की चिता की आग बुझने भी न पाई थी कि आतंकियों से लोहा लेते हुए पांच और जवानों के बलिदान होने की खबर आ गई। इनमें एक मेजर भी हैं। पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों को पुलवामा में ही मार गिराने के अभियान में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और डीआइजी समेत सात जवान घायल भी हुए हैं। इस अभियान में हताहत अधिकारियों और जवानों की यह संख्या यही बताती है कि कश्मीर में खतरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। निःसंदेह यह सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के अदम्य साहस और संकल्प का प्रमाण है कि उन्होंने मिलकर पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों को सौ घंटे के अंदर खोजकर मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन उनका दमन करने के क्रम में उन्हें जो क्षति उठानी पड़ी वह चिंता का विषय है। यह सही है कि घिनौनी नफरत से भरे और मरने-मारने पर आमादा आतंकियों के सफाए के हर अभियान में जोखिम होता है, लेकिन आखिर कश्मीर में ऐसा कब तक चलता रहेगा? जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कश्मीर में हमारे जवान कब तक इसी तरह बलिदान देते रहेंगे? यह सवाल इसलिए गंभीर हो गया है, क्योंकि कश्मीर में आतंकियों की विष बेल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कश्मीर में देश भर के जवान तैनात हैं। जब वे वीरगति को प्राप्त होते हैं तो पूरे देश का वातावरण प्रभावित होता है। जवानों के परिजन कश्मीर में तैनात अपने लोगों की कुशल-क्षेम के लिए सदैव चिंतित बने रहें, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं। यह स्थिति आम जनता के मनोबल पर असर डालती है।

देश की जनता इसके प्रति तो सुनिश्चित है कि सेना और सुरक्षा बलों के आगे कश्मीर में सिर उठाने वाले आतंकियों की खैर नहीं, लेकिन वह यह जानने के लिए अधीर हो रही है कि आखिर देश के इस हिस्से में कब अमन-चैन कायम होगा? इस सवाल का जवाब देश के समस्त राजनीतिक नेतृत्व को देना होगा। यह अच्छा नहीं कि कश्मीर को शांत करने की कोई पहल होती नहीं दिख रही है। घाटी में एक ओर जहां अलगाव और आतंक के समर्थकों का सख्ती से दमन करने की जरूरत है वहीं देशभक्त कश्मीरियों को साथ लेने की भी। आखिर इस दिशा में कोई ठोस पहल कब होगी? क्या यह सही समय नहीं जब कश्मीर में अलगाव की मानसिकता का पोषण करने वाली धारा 370 खत्म की जाए और वहां के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं? वास्तव में जितनी जरूरत अमन-चैन पसंद लोगों को हर तरह से आश्वस्त करने की है उतनी ही इसकी भी कि आतंकियों के बचाव में पत्थरबाजी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वे फिर कभी पत्थर उठाने की जुर्रत न कर सकें। सहने की एक सीमा होती है। देश का राजनीतिक नेतृत्व यह समझे तो बेहतर कि कश्मीर के हालात से देश व्यथित है और उसकी व्यथा दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना उसकी जिम्मेदारी है।

स्वास्थ्य की चिंता

केंद्र ने झारखंड को तीन नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। लगभग 48 साल बाद एक साथ हजारीबाग, दुमका और पलामू में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते कदम की एक और बानगी है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 885 करोड़ की लागत वाले इन अस्पतालों के उद्घाटन के साथ-साथ तीनों शहरों के अलावा जमशेदपुर में 500-500 बेड के अस्पताल की भी आधारशिला रखी है। केंद्र की इस पहल के साथ ही राज्य के सभी प्रमंडलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का झारखंड का सपना साकार हो गया है। सरकार ने इससे पहले सामाजिक-आर्थिक जनगणना में सूचीबद्ध राज्य के लाखों परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़कर सरकार ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने की दिशा में सरकार की इस कोशिश की सराहना की जानी चाहिए। इससे इतर देखना यह भी होगा कि झारखंड स्वास्थ्य के राष्ट्रीय बेंचमार्क पर विकसित राज्यों की तुलना में अभी भी काफी पीछे है। राज्य के अस्पताल चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की घोर किल्लत झेल रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करें तो सृजित पदों की तुलना में चौथाई चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं हैं। सामान्य चिकित्सकों के भी लगभग यही हालात हैं। जरूरत है इस गैप को पाटने की। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य चिकित्सकीय इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ चिकित्सकों की किल्लत दूर करने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो झारखंड के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई करने के बाद लगभग 60 फीसद से अधिक डॉक्टर झारखंड छोड़कर बाहर के प्रदेशों में अपनी सेवा देने चले जाते हैं। आवश्यकता है ऐसे छात्रों को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने की। बहरहाल झारखंड में मेडिकल सीटों की कुल संख्या 350 है। नए कॉलेजों के खुलने से यह संख्या बढ़कर 650 हो जाएगी। सरकार की तैयारी मार्च अंत तक एक तथा आगामी वित्तीय वर्ष में दो और नर्सिंग कॉलेज खोलने की है। सरकार के इन प्रयासों से आने वाले दिनों में चिकित्सकों और नर्सों की कमी बहुत हद तक दूर हो जाएगी।

विषाक्त मानसिकता से बिगड़े हालात

बलबीर पुंज

कश्मीर में हमारी लड़ाई उस खतरनाक मानसिकता से है जिसमें घाटी के तमाम बाशिंदे 'काफिर-कुफ्र' के विषाक्त मकड़जाल में उलझे हुए हैं

जम्मू-कश्मीर का पुलवामा हाल में भीषण आतंकवादी हमले का शिकार बना। यक्ष प्रश्न यह है कि 1947 से लेकर अब तक स्वतंत्र भारत की अलग-अलग सरकारों के विभिन्न प्रयासों के बाद भी कश्मीर में हिंसक घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? क्यों बीते सात दशकों से घाटी की स्थिति जम्मू और लद्दाख की तुलना में अशांत है? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर उस वीडियो में है जिसे फिदायीन आदिल अहमद डार ने आत्मघाती हमला करने से पहले रिकॉर्ड किया था और जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। 14 फरवरी को पुलवामा के अवंतीपुरा में हुए भीषण आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना से देश के आम नागरिकों में जिस प्रकार का आक्रोश और शोक देखा जा रहा है उसका प्रतिबिंब 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में भी दिखा। उन्होंने कहा, 'देश के लोगों का खून खौल रहा है। आप सभी की भावनाओं को मैं भली-भांति समझ पा रहा हूं। सुरक्षाबलों को आगे की कार्रवाई के लिए, समय क्या हो, स्थान क्या हो और स्वरूप कैसा हो, यह तय करने की पूरी छूट दे दी गई है। देश के 130 करोड़ लोग मिलकर मुंहतोड़ जवाब देंगे।'

ऐसा नहीं है कि कश्मीर में पहली बार कोई आतंकवादी हमला हुआ है। बीते कई दशकों से घाटी इस प्रकार की घटनाओं को झेल रही है, जिस पर समाज स्वाभाविक रूप में आक्रोशित भी होता है। भारी मात्रा में विस्फोटक से भरे वाहन को 2,500 से अधिक सीआरपीएफ जवानों के काफिले से टकरा देने वाला फिदायीन कौन था? आखिर वह अपनी जान देकर उन लोगों की जान क्यों लेना चाहता था, जिन्हें वह जानता तक नहीं था? इस मानसिकता को किस विचारधारा ने जन्म दिया? 1999 में जन्मा आदिल अहमद डार पुलवामा के ही काकपोरा का निवासी था और 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। आतंकी बनने से पहले वह एक स्थानीय आरा मशीन पर काम करके लकड़ी की पेटियां बनाता था और मार्च 2018 में उसने आतंकवाद की राह पकड़ ली। प्रारंभ में वह जिहादी जाकिर मूसा के साथ रहा, फिर जैश-ए-मोहम्मद का हिस्सा बन गया, जहां पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकी कामरान गाजी ने उसे प्रशिक्षण दिया। यही गाजी गत दिवस सेना के हाथों मारा गया।

आखिर आदिल मरने-मारने को क्यों तैयार हो गया? पुलवामा हमले से पहले उसके द्वारा बनाए वीडियो संदेश से ही काफी हद तक उसका खुलासा हो जाता है। वह कहता है, 'अभी मैंने अपने हिस्से का कर्ज और फर्ज अदा किया है। अपनी जान का नजराना पेश करके उम्मत (इस्लामी जगत) का सिर फिर से बुलंद किया है। मुझ जैसे हजारों लोग तुम्हारी (भारत की) तबाही का सामान लिए अपनी मंजिल को पाने के लिए बेताब बैठे है। हमारा जिहाद गजवा-ए-हिंद की मुबारक कड़ी है, जिसे तोड़ना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं है। हम हर दिन पहले से अधिक ताकतवर हो रहे हैं। हमारी शहादत इस्लाम के लिए कुर्बानी है।'

अवधेश राजपूत

आदिल जैसे जिहादियों का दर्शन अन्य धर्मावलंबियों को 'काफिर-कुफ्र' घोषित करता है। इस विध्वंसक मानसिकता को भारत सदियों से झेल रहा है। चाहे वह आठवीं शताब्दी से विदेशी आक्रांताओं द्वारा लूटपाट, मंदिरों को ध्वस्त, मतांतरण और गैर-मुस्लिमों की हत्या हो या फिर 19वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम अलगाववाद का बीजारोपण हो या फिर 1946 में बंगाल में 'सीधी कार्रवाई' और 1947 में भारत का रक्तरंजित विभाजन हो, 1980-90 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो या फिर कालांतर में जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का जन्म।

सभ्य समाज दशकों से इस विषैले चिंतन पर ईमानदार चर्चा करने से बच रहा है, यह उसका ही परिणाम है कि उस विषबेल ने आज पूरे विश्व को जकड़ लिया है। पुलवामा में जिस प्रकार विस्फोटक से लदे वाहन से आतंकवादी हमला किया गया, वैसा कश्मीर में पहली बार हुआ है। इसी तरह की बर्बरता हम कुछ वर्ष पहले-फ्रांस, बर्लिन और लंदन जैसे यूरोपीय शहरों में देख चुके है, जिसमें वाहन के माध्यम से ही दर्जनों निरपराधों को कुचलकर मार डाला गया। स्पष्ट है कि कैंसर रूपी यह दर्शन भयावह रूप ले चुका है। इस रुग्ण मानसिकता का एक बड़ा कारण मजहबी शिक्षा पद्धति भी है, जिसका सबसे बड़ा दोष यह है कि उनमें सामाजिक, वैचारिक और साहित्यिक समरसता का नितांत अभाव रहता है। प्रारंभिक परवरिश में बाहरी दुनिया से कटाव छात्रों को अन्य समुदाय, विशेषकर विविधताओं से भरे समाज में-आचार-विचार, जीवन दर्शन, शैली और संस्कृति से अपरिचित रखता है। यदि बाल्यकाल से ही इन बच्चों को एक विशेष प्रकार का वातावरण मिले तो स्वाभाविक तौर पर उनका दृष्टिकोण, वेशभूषा, भाषा और इतिहास की समझ और आकांक्षाएं- शेष समाज से भिन्न हो जाएंगी। इसी पृष्ठभूमि में जब उनके तौर-तरीकों में समय के अनुसार परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो उसे मजहब पर हमला करार दिया जाता है। कटु सत्य तो यह है कि मजहबी शिक्षण व्यवस्था को प्रोत्साहन और जिहादी कट्टरता-आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का अभियान, एक दूसरे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। शिनजियांग, गांसू सहित कुछ अन्य चीनी प्रांतों में जिहादी कट्टरता, अलगाववाद और आतंकवाद से निपटने के लिए चीन की वामपंथी सरकार ने उग्र अभियान छेड़ा है। वहां मदरसा शिक्षा प्रणाली प्रतिबंधित है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों के मजहबी कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक है। सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम पुरुषों को दाढ़ी रखने तो महिलाओं को बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है।

एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, इस्लाम के चीनीकरण हेतु अप्रैल 2017 से चीनी सरकार ने मुस्लिम समुदायों के 10-20 लाख लोगों को शिविरों में अनिश्चितकाल के लिए बंद किया हुआ है। सरकारी निर्देश नहीं मानने वालों को घंटों भूखा रखा जाता है और एकांत कोठरियों में दिन-रात खड़े रहने की सजा दी जाती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों के नियमित दौरे से वहां इस्लामी मान्यताओं का अनुपालन लगभग वर्जित हो गया है। निर्विवाद रूप से भारत, अमेरिका सहित कोई भी पंथनिरपेक्ष, बहुलतावादी और लोकतांत्रिक देश-आतंकवाद और हिंसक अलगाववाद से निपटने के लिए चीनी नीतियों का अनुसरण कभी नहीं करेगा। इसके बावजूद इस्लामी जगत दुनिया भर की शिकायत करता है, लेकिन चीन को लेकर मौन साधे रहता है। क्या कश्मीर समस्या का अंत संभव है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि घाटी के अशांत होने का मुख्य कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, विकास, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन में नहीं है। कश्मीर में हमारी लड़ाई उस विषाक्त मानसिकता से है जिसमें घाटी के तमाम बाशिंदे 'उम्मत बनाम काफिर-कुफ्र' के विषाक्त मकड़जाल में उलझे हुए हैं। जिस दिन कश्मीर इस मकड़जाल से मुक्त हो जाएगा उस समय से ही वह भी शेष भारत की भांति सामान्य क्षेत्र हो जाएगा।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

राष्ट्रभाव फिर से जगाने की जरूरत

डॉ. महेश भारद्वाज

यह राष्ट्रीयता की कमी है कि कई बार सरकार का विरोध करते-करते लोग राष्ट्र विरोध की सीमा तक पहुंच जाते हैं

कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों के काफिले पर हुए जघन्य हमले ने एक बार फिर विश्व समुदाय को आतंकवाद के प्रति गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए विवश कर दिया है। बढ़ते वैश्वीकरण के बावजूद अपने-अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की जो प्रवृत्ति पिछले कुछ बरसों में बलवती हुई है उसकी जड़ में भी यही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है। इसी का परिणाम है कि आज धीरे-धीरे ही सही अच्छे और बुरे आतंकवाद के बीच का भेद भी मिटने लगा है। खेमों में बंटे देशों में अपनी राष्ट्रीयता के प्रति अपेक्षाकृत अधिक लगाव ने भी जोर पकड़ा है। पिछले कुछ बरसों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस और चीन जैसे विकसित देशों द्वारा राष्ट्र सर्वोपरि के लिए मुखरता से दी जाने वाली दलीलों को इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। इन देशों की जनता ने देश और राष्ट्रीयता की बात पुरजोर तरीके से करने वाले राजनीतिक नेतृत्व को पसंद भी किया है। अब अपने राष्ट्रीय हितों की खुले तौर पर पैरवी करने में किसी को कोई झिझक भी नहीं है और तो और कुछ देश अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की आलोचना की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पिछले दिनों दिए गए अमेरिका के इस्तीफे और यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के ब्रिटेन के निर्णयों की पृष्ठभूमि में राष्ट्र सर्वोपरि की इस भावना को देखा जा सकता है।

राष्ट्रीयता के प्रति इस अंतरराष्ट्रीय झुकाव से अलग हमारे देश में माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। यहां राष्ट्रीयता की आवाज के तेजी पकड़ते ही कुछ लोगों को कई तरह की आशंकाएं होने लगती हैं और राष्ट्रीयता के पक्ष में उठने वाली आवाजों के पीछे लोकतांत्रिक विचारों को दबाने की कोशिश तलाशने के प्रयास होने लगते हैं। चूंकि राष्ट्रीयता की आवाज बुलंद करने संबंधी प्रयासों को सरकार का समर्थन स्वाभाविक होता है तो सरकार का विरोध कर रही ताकतें भी सक्रिय होने लगती हैं। इसमें कई बार तो ऐसा भी होता है कि सरकार विरोधी ताकतों को यह पता ही नहीं चल पाता कि सरकार का विरोध करते-करते वे कब राष्ट्रीयता की भावना का भी विरोध करने की स्थिति में पहुंच जाती हैं। इस स्थिति का सर्वाधिक फायदा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्व उठा लेते हैं और सुरक्षा बलों द्वारा नेस्तनाबूद किए गए संगठन भी ऑक्सीजन पा जाते हैं। ऐसी स्थिति राष्ट्र के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार का विरोध और खासकर अंध विरोध करने वालों को सावधानी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सुरक्षा बलों के मनोबल से भी है। सामान्य माहौल में तो सरकार और व्यवस्था की आलोचना और विरोध जायज है, लेकिन संकट के समय ऐसा आचरण करते समय राष्ट्र को होने वाले नुकसान के बारे में भी सजग रहने की जरूरत है। कहीं आलोचना के अति उत्साह में राष्ट्र, समाज और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी ही विस्मृत न हो जाए। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह सब देश में मौजूद लोकतांत्रिक माहौल और उसके तहत नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति की आजादी के तहत होता है। यह आजादी कुछ जिम्मेदारी की भी मांग करती है। संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी को कुछ लोग अपने पक्ष में इस कदर परिभाषित कर लेते हैं कि उन्हें उस संविधान की मर्यादा तक का खयाल नहीं रहता जिसने बिना किसी भेद-भाव के यह आजादी सुलभ कराई है।

आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों की तह में जाकर देखने की आवश्यकता है। इन गतिविधियों को संचालित करने वाले तत्व अपनी लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई के आवरण में लपेटकर जनता को परोसने की कोशिश करते हैं। जनता उनकी इस चालाकी को समझ नहीं पाती। जैसे आदिवासी क्षेत्रों के सीधे-सादे लोगों की आर्थिक तंगी और पिछड़ेपन का पूरा फायदा उठाया गया है और उन्हें तरह-तरह के सब्जबाग दिखाकर अपने ही राष्ट्र से लड़ने में लगाकर रखा गया है वैसा ही कुछ कश्मीर में किया गया है। कश्मीर तब अशांत और अलगाव से ग्रस्त है जब वह आर्थिक रूप से देश के कई हिस्सों से कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। कश्मीर में तमाम तत्व ऐसे हैं जो शत्रु देश से तमाम तरह का सहयोग और समर्थन खुलेआम ले रहे हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर हमें एक राष्ट्र के रूप में बहुत ही गंभीरता से विचार करने और राष्ट्रीयता की भावना को और अच्छे से सींचने की जरूरत है। राष्ट्रीयता की भावना ही वह जज्बा पैदा करने की ताकत रखती है जिससे लोग व्यक्तिगत हित छोड़कर देश के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत होते हैं।

इस भावना को केवल देश की सीमा की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी जरूरत देश के अंदर सिर उठाने वाली हर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लड़ने के लिए भी है। ऐसे में जरूरत है स्वाधीनता संग्राम के दौरान उमड़ी राष्ट्रभक्ति को फिर से जगाने की, जिसने लोगों को राष्ट्रहित में आइसीएस जैसे सर्वोच्च पदों से भी त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया था। अब समय आ गया है आम लोग राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य समझें और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने-कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करें। यही वह भावना है जो हमारे सैनिकों को देश की सीमा पर विकट से विकट परिस्थितियों में और अन्य सुरक्षाबलों को देश के आंतरिक हिस्सों में साहस के साथ विध्वंसक तत्वों से लड़ने का अदम्य साहस और हौसला प्रदान करती है। राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत यज्ञ में हर नागरिक के योगदान की अपेक्षा है। लोगों को ही यह परवाह करनी होगी कि हर कोई इसमें योगदान दे। इस अपेक्षा में ईमानदारी से टैक्स देना भी आता है और सामान्य नियम-कानूनों का स्वतः पालन करना भी। ऐसे तमाम कार्य हैं जिनमें देश के बहुत सारे संसाधनों का इसलिए बेवजह इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ लोग अपना काम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर नहीं करते। कुछ लोग राष्ट्रीयता की भावना के अत्यधिक बलवती होने को अंतरराष्ट्रीयता में बाधक मानते हैं, लेकिन मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिवेश में हमारे यहां राष्ट्रीयता की भावना को पूरे वेग के साथ परवान चढ़ाने की दरकार है। राष्ट्रीय अस्मिता को मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए उच्चकोटि की राष्ट्रभक्ति आवश्यक है। जाति, भाषा, रंग-रूप, संस्कृति संबंधी विविधता होते हुए भी राष्ट्रीयता ही वह भावना है जो सभी को एकसूत्र में बांधे रख सकती है। देशवासियों में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराने और उनमें अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए भी यह आवश्यक है।

(लेखक आइपीएस अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शब्दबीज

वाणी-विभूषित शब्द दैव-सृष्टि से मानव को मिले अनुपम उपहार हैं। वाणी परम पावन भागीरथी-गंगा सदृश है। जीवन के आहार-व्यवहार में तप-तप कर जिस प्रकार गोमुख से निकली जलधारा असंख्य मीलों की यात्रा कर गंगाजल होने के अमरत्व एवं महत्व को प्राप्त करती है, उसी प्रकार शब्द भी उच्चारण से आचरण तक की निष्ठा एवं पवित्रता की भट्ठी में तप-तप कर मंत्र सृष्टि की शाश्वतता को प्राप्त होने का अपना सफर तय करने में सफल होते हैं। मंत्र जीवन-साधनारूपी यज्ञशाला की कल्याणकारी अग्नि में आचरण एवं पवित्रता से पगे, तपे, सुचिंतित और सोद्देश्य शब्दों का ही परिष्कृत रूप है। शब्दों के सदुपयोग की सकारात्मकता का मार्ग शाश्वत सृजन एवं मंत्र-सृष्टि के पावन धाम की ओर ले जाता है जो इसके प्रयोक्ताओं को आनंद, उत्साह, लक्ष्य, शांति और सफलता के चिरंतन सुखों अथवा सुफलों से लाभान्वित करता रहता है, लेकिन शब्दों का दुरुपयोग मानव को नकारात्मकता के मार्ग पर चलकर निराशा, विध्वंस, पीड़ा, पश्चाताप के अंधकारमय गड्ढों में धकेल कर यह दुर्लभ जीवन नष्ट करने के लिए प्रेरित करता रहता है।

शब्द की उर्वरता एवं सोच की सकारात्मकता मानव के लघु जीवन-खंड को ऐतिहासिक एवं स्मरणीय बनाकर विश्व में चर्चित कर देती है। शब्द के प्रति उदासीनता एवं सोच की नकारात्मकता, दुर्लभ जीवन को ईर्ष्या, द्वेष और कुविचारों के घुनों से खिलवाकर इसे दानवी कृत्यों का स्वामी बनाकर युग-युगों तक के लिए कलंकित कर देती है। एक मंत्ररूपी शब्द हमारी अज्ञानतारूपी अंगुली थाम हमें सदुद्देश्य की ओर प्रेरित कर जीवन का कल्याण कर सकता है, जबकि एक दुष्प्रेरक शब्द हमें हमारे सद्मार्ग से भटकाकर किन्हीं गलत उद्देश्यों की ओर प्रेरित कर हमारे इस दुर्लभ जीवन को सदा-सदा के लिए बर्बाद कर मानवता को कलंकित कर सकता है।

ईश्वर ने विवेकरूपी मस्तिष्क मानव को इसी सद्प्रयोजन के लिए उपहार में प्रस्तुत किया है ताकि वह इसका प्रयोग सही दिशा में कर पशुता में परिवर्तित होते अपने जीवन को नष्ट होने से बचा ले। आइए प्रभु से उपहार में मिले इस शब्दबीज का सदुपयोग कर मानवता के कल्याण और ज्ञान के अनंत क्षितिज को नव आयाम दें।

डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'

घरेलू महिलाओं की समस्या

डॉ. ऋतु सारस्वत

घरेलू महिला के त्याग, समर्पण और प्रेम की अवहेलना समाज को एक घातक दिशा की ओर ले जा रही है

फरवरी के प्रथम सप्ताह में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक 2016 में अपनी जान लेने वालों में 44.2 प्रतिशत से अधिक लोग भारत और चीन के थे, परंतु यह रिपोर्ट इस तथ्य से चौंकाती है कि भारत में किसानों की तुलना में चार गुना अधिक घरेलू महिलाओं ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या राष्ट्रीय चर्चा एवं चुनावी मुद्दों का विषय रहा है, परंतु घरेलू महिलाओं की 'आत्महत्याएं' समाज के किसी भी वर्ग में चर्चा का विषय नहीं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि पितृसत्तात्मक समाज में उनका महत्व नगण्य है। शोधों में मूलतः बाल विवाह और घरेलू हिंसा को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाता है और ये कारण हैं भी, इससे कतई इन्कार नहीं।

आमतौर पर 'आत्महत्या' एक निजी मामला माना जाता है, परंतु इससे इतर यह एक सामाजिक कृत्य है, क्योंकि समाज ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए विवश हो जाता है। 'बाल विवाह' इसका जीवंत उदाहरण है। जहां अल्पायु में बच्चियों के ऊपर पारिवारिक दायित्वों को लाद दिया जाता है, जिसके चलते वे अवसादग्रस्त हो जाती हैं और कई बार इसकी परिणति आत्महत्या होती है। अध्ययन यह भी बताते हैं कि घरेलू हिंसा महिलाओं के आत्मसम्मान को इस कदर चोट पहुंचाती है कि वे अवसाद का शिकार हो जाती हैं। आत्महत्या पर किए गए कई अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग 80 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिलाएं अवसाद से ग्रसित थीं, परंतु इन सबसे इतर भारतीय परिवारों के भीतर बीते दशकों में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह समाज के एक ऐसे नकारात्मक बदलाव की ओर संकेत कर रहा है, जिसे समय रहते यदि सुधारा नहीं गया तो आने वाले समय में स्थितियां घातक हो जाएंगी।

प्रथम दृष्टि में घरेलू महिलाओं का जीवन मानसिक तनाव से दूर घर की सुरक्षित दीवारों के बीच सुकून भरा दिखता है। चूंकि घरेलू महिलाओं का घर की आर्थिक आवश्यकताओं में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं होता इसलिए उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। घर के महत्वपूर्ण निर्णय में सहभागिता तो दूर अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता, उनके भीतर हीनभावना को जन्म देती है। 'अवसाद' का एक बहुत बड़ा कारण दो व्यक्तियों के मध्य 'तुलना' भी होता है। जब उनकी तुलना उन्हीं के समकक्ष शिक्षित, परंतु कामकाजी महिला से की जाती है और उन्हें कमतर सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है।

'घर पर निठल्ले बैठे रहने' का उलाहना भारत की हर घरेलू महिला को समय बे-समय झेलना पड़ता है और यह उनके मानसिक संत्रास का एक बड़ा कारण है। निरंतर मिलने वाली उपेक्षाएं और अकेलापन उन्हें यह सोचने पर कई बार विवश कर देते हैं कि उनके परिवार को उनकी आवश्कता नहीं है। यही भावना आत्महत्या का कारण बनती है। घरेलू महिला के त्याग, समर्पण और प्रेम की यूं अवहेलना समाज को एक घातक दिशा की ओर ले जा रही है इसलिए अब यह सोचना उचित है कि जो संपूर्ण परिवार की केंद्र है क्या वह उस सम्मान की हकदार नहीं जो परिवार के मुखिया को मिलता है?

(लेखिका ऐसोसिएट प्रोफेसर हैं)

चरमपंथ से वैचारिक युद्ध की जरूरत

शंकर शरण द्वारा लिखित 'हथियार से नहीं विचार से लड़ने की जरूरत' लेख में धर्म आधारित जिस इस्लामिक चरमपंथी विचार की चर्चा की गई है, वह अलगाववाद और जिहादी आतंकवाद को ऑक्सीजन देने वाला एक घातक विचार है। धर्मोन्मादी जिहादी इस चरमपंथी विचार को उत्प्रेरक बनाकर इस्लाम के नाम पर मरने-मारने के लिए आतुर आत्मघाती आतंकवादियों को उनका ब्रेन-वॉश कर तैयार करते हैं। आजादी का सूरज निकलने से पहले ही देश-विभाजन की कालिमा फैलाने वाला यही चरमपंथी विचार था। भारत-विभाजन का कारक बनने वाले इस चरमपंथी विचार को यदि उसी समय पूरी ताकत के साथ कुचल दिया जाता तो आज अलगाववाद को हवा देने वाले इस्लामिक चरमपंथ को हिंदू बहुल भारत में पैर पसारने का अवसर नहीं मिलता। अपने जन्म-काल से भारत को आघात दर आघात देने वाले पाकिस्तान को ताकत देने वाला यही चरमपंथी विचार है। पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी सरगना अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे धर्मोन्मादी अपनी इसी चरमपंथी वैचारिकता से मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में आतंक की फसल बोने में कामयाब होते रहे हैं। इनके इस भारत विरोधी विचार को खाद-पानी देने के लिए हुर्रियत जैसे अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर की आजादी का राग अलाप कर जिहादी आतंकवाद को क्रांति का वैचारिक चोला पहनाने की हर संभव कोशिश की है। कुछ छात्र और बुद्धिजीवी भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाते नजर आते रहे हैं। ऐसे में हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई के साथ-साथ अब वैचारिक स्तर पर इस चरमपंथी विचार से भी समानांतर युद्ध की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

स्वदेशी ताकत का परिचायक

रमेश कुमार दुबे ने अपने आलेख 'कायापलट की राह पर रेलवे' के माध्यम से रेलवे के क्षेत्र में हुए विकास को उजागर किया है। भारत वैश्विक पटल पर ताकतवर देश के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी क्षेत्रों में स्वदेशी निर्माण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जब कोई भी वस्तु अपने ही देश में निर्मित होगी तो उसके निर्माण में लगाया हुआ धन अपने ही देश में रहेगा। इससे रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे और हमारे देश के नागरिकों खासतौर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि जब हमारा देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों से आगे बढ़ेगा तो स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की मांग विदेशों में भी बढ़ेगी, जिसके निर्यात से प्राप्त धन का प्रयोग अपने देश के विकास में लगाया जा सकेगा। वंदे एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण एक स्वदेशी कंपनी ने किया है। यह बेहद गर्व की बात है। इस ट्रेन की खास बात है इसकी बनावट, जो देशवासियों के साथ-साथ विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसके अतिरिक्त यह सभी सुविधाओं से लैस है तथा इससे सफर करने से यात्रियों के समय की भी बचत होगी। स्वदेशी निर्मित वस्तुएं स्वदेशी ताकत का परिचायक हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों से हर क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण के सार्थक प्रयास अपेक्षित हैं।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

एक अस्थाई विकृति

शंकर शरण का आलेख 'हथियार से नहीं विचार से लड़ने की जरूरत' पढ़ते हुए मुझे महान दार्शनिक योगीराज अरविंद के पाकिस्तान संबंधी शब्द स्मरण हो आए। उन्होंने कहा था, 'पाकिस्तान एक अस्थाई विकृति है, जिसने एक सनातन सत्य भारत को ढंक लिया है। सच्चा भारत तो अखंड भारत ही है, जो तमाम बाह्य राजनीतिक परिस्थितियों, जो निरंतर बदलती रहती हैं, के बावजूद एक कालातीत सत्य है। विभाजन दूर होना ही चाहिए और वह दूर होगा भी-इसमें संशय करने का हमें अधिकार नहीं। वह भारत की नियति है।' जो लोग पाकिस्तानियों को 'इस्लाम खतरे में है' कहकर भारत के विरुद्ध भड़काते रहते हैं, उन्हें वहां के एक मशहूर शायर का जवाब पढ़ने योग्य है, 'खतरे में इस्लाम नहीं, खतरा है जरदारों को। गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को।' हमें इस विचार को आज प्रोत्साहन देने की जरूरत है, लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि पाकिस्तान में इस विचार को शक्तिशाली करने के लिए एक बार विभाजनकारी मनोवृत्ति का पूर्ण सैनिक पराभव भी जरूरी है। इसलिए युद्ध का विकल्प भी अपनाना पड़ेगा, तभी विभाजनकारी दीवारें गिराने में सहायता मिलेगी।

अजय मित्तल, मेरठ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।